हम राजस्थानी • चुनौतियां बनीं विकास में बाधा

औद्योगिक समस्याएं खत्म हों, तो बदलेगी राज्य की तस्वीर

इकोनॉमी

प्रदीप मेहता
सेक्रेटरी जनरल कट्स इंटरनेशनल
psm@cuts.org

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में कई अवसर मौजूद हैं। जयपुर में आभूषण, वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग प्रमुख हैं। जोधपुर में फर्नीचर, हथकरघा और कृषि उपकरणों के उद्योग पनप रहे हैं। उदयपुर खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योगों का केंद्र है। कोटा पावर प्लांट, सीमेंट और शिक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग का केंद्र है। पाली वस्त्र उद्योग और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए जाना जाता है। नीमराना में जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जहां डाइकिन, निसिन ब्रेक, मायटेक्स पॉलिमर और निप्पॉन पाइप सहित 50 से अधिक जापानी फर्मों ने 6,000 करोड़ का निवेश किया है।

इसी तरह भिवाड़ी ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का केंद्र है। अलवर में विविध औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं, जो दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का लाभ उठाती हैं। बालोतरा टेक्सटाइल और डाइंग इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र है। बाड़मेर क्षेत्र में स्थित राजस्थान रिफाइनरी और अन्य तेल एवं गैस परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, जो राज्य को हरित ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बना रही हैं।

लेकिन, जल संकट, पर्यावरणीय प्रदूषण, ऊर्जा की उच्च लागत व बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। नौकरशाही में बार-बार होने वाले स्थानांतरण भी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। इससे दीर्घकालिक औद्योगिक योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की कमी गंभीर समस्या है। अलवर और भीलवाड़ा में भूजल स्तर में तेज गिरावट आई है, जो चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान के लिए जयसमंद बांध और विजय मंदिर झील जैसे वैकल्पिक जलाशयों का उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से जल संकट और भी गहरा गया है। रीको से सीमित समर्थन के कारण उद्योग बोरवेल और निजी आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भर हैं। भूजल पर यह निर्भरता दीर्घकालिक स्थिरता संबंधी चिंताओं को बढ़ाती है, जिससे केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करने में कठिनाई होती है। टूटी सड़कें, खराब जल निकासी, खराब व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग की समस्या और सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता उद्योगों के लिए बड़ी बाधा है। भिवाड़ी और नीमराना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। IQAir की रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। उद्योगों के लिए विश्वसनीय और किफायती बिजली आपूर्ति बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे- सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। कई औद्योगिक क्षेत्रों में कचरा निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, पाली, अजमेर, सीकर, भिवाड़ी जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में उद्योगों के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, व्यापार को बढ़ावा मिला है और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है।

संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। 13 जिलों में जल संकट दूर करने के लिए ईआरसीपी बनाई गई है। 2.82 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ने से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। 'राइजिंग राजस्थान' का उद्देश्य औद्योगिक विकास को नई गति देना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी-2025 और राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जैसी नीतियां लागू की गई हैं। इससे वस्त्र एवं परिधान उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, डेटा सेंटर इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में सुधार होगा। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा, ताकि राजस्थान को भारत के बड़े औद्योगिक हब के रूप में स्थापित किया जा सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)